गुरुवार, 15 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

स्पेन से हार के बाद एम्बाप्पे का बड़ा बयान, बोले- रणनीति पर नहीं खेल पाए

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'वाराणसी' को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी महेश बाबू बनेंगे राम

Page-05

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी और इस हमले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन

हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता हासिल की है। जम्मू की विशेष NIA अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सरगना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी कर दिया है। अदालत का यह आदेश NIA द्वारा 6 जुलाई को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर आया है, जिसमें हाफिज सईद को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।NIA के अनुसार, इस हमले की योजना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी नेटवर्क ने तैयार की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि हाफिज सईद ने अपने संगठन के माध्यम से हमले की साजिश रची, आतंकियों को दिशा-निर्देश दिए और सीमा पार से उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। चार्जशीट में कई तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ-साथ पूछताछ और खुफिया

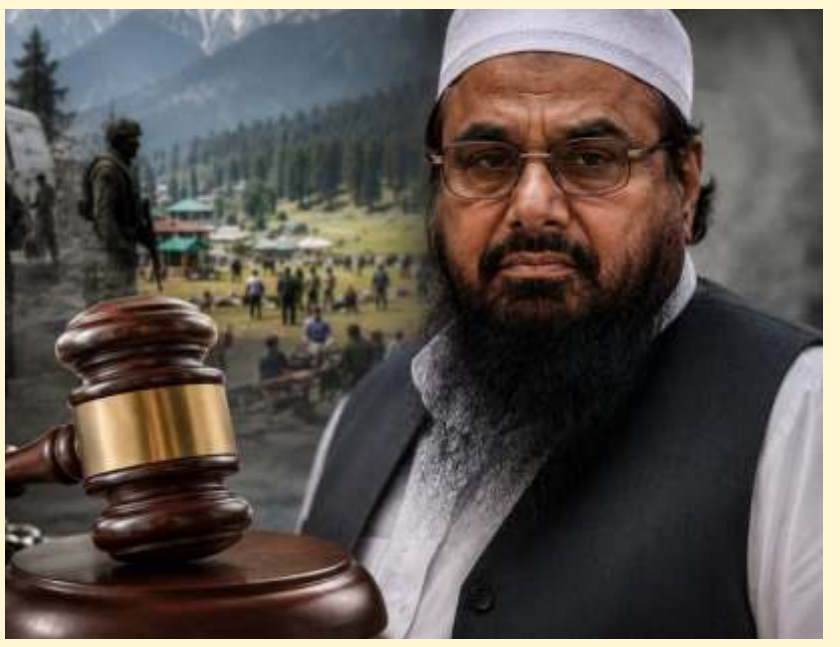

एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों का भी उल्लेख किया गया है।22 अप्रैल 2025 को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे हाल के वर्षों के सबसे गंभीर आतंकी हमलों में से एक माना था। घटना के बाद केंद्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था और NIA को मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई थी।अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद अब हाफिज सईद की अनुपस्थिति में भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। यदि वह भारतीय अदालत के समक्ष पेश नहीं होता है, तो कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। NIA अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों, सहयोगियों और आतंकी नेटवर्क की वित्तीय एवं लॉजिस्टिक कड़ियों की भी जांच तेज कर रही है।भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों को लगातार खारिज करता आया है। हालांकि, भारत का कहना है कि उसके पास आतंकवादी संगठनों और उनके संचालकों की भूमिका से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत की ताजा कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के पक्ष को मजबूती दे सकती है।

RTI में बड़ा खुलासा: रेलवे की 1,068 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा

भारतीय रेलवे की हजारों करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक देशभर में रेलवे की 1,068.54 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा दर्ज किया गया है। यह क्षेत्रफल लगभग 1,500 फुटबॉल मैदानों के बराबर बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह जमीन देश के कई राज्यों में फैली हुई है और इसका बड़ा हिस्सा शहरी तथा व्यावसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित है।RTI के आंकड़े यह भी बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कम होने के बजाय लगातार बढ़ा है। हालांकि रेलवे समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाता रहा है, लेकिन कानूनी विवाद, स्थानीय विरोध, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और संसाधनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में कब्जे अब भी बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे की इन जमीनों का बाजार मूल्य हजारों करोड़ रुपये हो सकता है और यदि इन्हें मुक्त कराया जाए तो रेलवे की आय बढ़ाने और नई परियोजनाओं में इनका उपयोग किया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाए भी गए हैं, लेकिन नए कब्जे होने की समस्या बनी हुई है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवेदनशील इलाकों की नियमित निगरानी की जा रही है और भविष्य में आधुनिक तकनीक की मदद से भूमि प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा।

E20 पेट्रोल विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले- सही माइलेज का पता केवल अधिकृत टेस्टिंग मशीनों से ही चलेगा

देश में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम वाहन चालक अपनी कार या बाइक का वास्तविक माइलेज खुद सटीक तरीके से नहीं माप सकते। उनके अनुसार ईंधन की वास्तविक खपत का सही आकलन केवल अधिकृत डीलरशिप और प्रमाणित टेस्टिंग उपकरणों के जरिए ही किया जा सकता है। गडकरी का यह बयान उस समय आया जब एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी कार का माइलेज पहले की तुलना में कम हो गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि केवल व्यक्तिगत अनुभव या वाहन के डिस्प्ले पर दिखने वाले आंकड़ों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।गडकरी ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन का माइलेज कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करता है। इनमें सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, वाहन की सर्विसिंग, टायर का प्रेशर, ड्राइविंग स्टाइल, इंजन की स्थिति और मौसम जैसी कई बातें शामिल होती हैं। ऐसे में केवल E20 पेट्रोल को माइलेज कम होने का कारण बताना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी फैसले विस्तृत तकनीकी परीक्षण और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर लेती है।केंद्रीय मंत्री ने यह भी दोहराया कि E20 पेट्रोल का उद्देश्य केवल ईंधन बदलना नहीं है, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना भी है। इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अधिक उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, कई वाहन मालिकों और विपक्षी दलों का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद माइलेज में गिरावट आई है और सरकार को इस विषय पर स्वतंत्र एवं पारदर्शी अध्ययन सार्वजनिक करना चाहिए।

होर्मुज में कथित ईरानी मिसाइल हमले के बाद भारत सख्त

होर्मुज जलडमरूमध्य में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो तेल टैंकरों पर हुए कथित ईरानी मिसाइल हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया है। इस घटना में एक भारतीय नाविक की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर सामने आने के बाद भारत सरकार ने कड़ा राजनयिक रुख अपनाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरान के उप-राजदूत को तलब कर घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने नागरिकों और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सरकार ने इस घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों को जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने चाहिए। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर निर्यात होने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

चारा घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बहुचर्चित देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसके तहत लालू यादव को जमानत मिली हुई है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि लालू यादव की अपील पर जल्द सुनवाई की जाए, ताकि मामले का अंतिम निपटारा बिना अनावश्यक देरी के हो सके।यह मामला देश के सबसे चर्चित आर्थिक घोटालों में से एक चारा घोटाले से जुड़ा है, जिसमें बिहार के पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों और दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में लालू यादव को पहले दोषी ठहराया जा चुका है और वह सजा भी काट चुके हैं। बाद में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को देखते हुए उन्हें जमानत दी गई थी। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव की जमानत फिलहाल जारी रहेगी। आरजेडी ने इसे न्यायपालिका में विश्वास की जीत बताते हुए कहा कि अदालत ने तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है। वहीं CBI ने कहा कि वह आगे भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष मजबूती से

रखेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच यह फैसला आरजेडी के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। लालू यादव की सक्रियता पहले से बढ़ी है और पार्टी उन्हें आगामी राजनीतिक रणनीति का अहम चेहरा मान रही है। अब सभी की नजर झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले की विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ेगी।

ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम

अब अदालत के फैसले पर टिकी सबकी नजर

वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश फिलहाल सफल नहीं हो सकी है। अदालत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर देते हुए वाराणसी के मध्यस्थता केंद्र में पेश होने का सुझाव दिया था। हालांकि, दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और साफ कर दिया कि वे इस संवेदनशील मामले का समाधान केवल कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अंतिम फैसले के जरिए ही चाहते हैं।हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला केवल संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका समाधान किसी समझौते से नहीं बल्कि न्यायालय के निर्णय से होना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने भी स्पष्ट किया कि वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखेगा और मध्यस्थता के बजाय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करता है। दोनों पक्षों के इस रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकी।ज्ञानवापी विवाद पिछले कई वर्षों से देश के सबसे चर्चित धार्मिक और कानूनी मामलों में शामिल है। इस मामले में पूजा-अधिकार, धार्मिक स्थल की प्रकृति और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े कई मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान आपसी सहमति से निकाला जा सकता है। लेकिन दोनों पक्षों के इनकार के बाद अब मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की अदालतों में होने वाली सुनवाई इस बहुचर्चित मामले के भविष्य की दिशा तय करेगी।

टैरिफ से पहले भारत का मास्टरस्ट्रोक, फोर्स्ड लेबर वाले आयात पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका के प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ से पहले भारत ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप नियम सख्त किए और अमेरिकी जांच व एकतरफा टैरिफ नीति पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका भारत पर एक और टैरिफ लगाने की तैयारी में था। लेकिन उससे पहले भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे ट्रंप प्रशासन की पूरी रणनीति को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका का आरोप था कि भारत जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा और इसी आरोप के आधार पर ट्रंप प्रशासन भारत पर एक और टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अमेरिका अपना फैसला सुनाता उससे पहले ही भारत में ऐसा दांव चल लिया जिसने वाशिंगटन की पूरी दलील को चुनौती दे दी। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान कर दिया कि अब जबरन मजदूरी से बने किसी भी सामान का भारत में आयात नहीं होगा। यानी जिस मुद्दे को आधार बनाकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था। उसी मुद्दे पर भारत ने पहले ही अपना कानून सख्त कर दिया। दरअसल यह मामला बहुत पेचीदा है। कुछ समय पहले अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर ने भारत समेत 60 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामानयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इन देशों में भारत और चीन जैसे देश शामिल थे और इसी जांच के आधार पर अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों के सामान पर 12 1/2% अतिरिक्त टेरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। अगर यह टेरिफ लागू होता है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। जिससे कई भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका की इस तैयारी के बीच भारत ने भी तेजी से कदम उठाया। 13 जुलाई को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने एक नई अधिसूचना जारी की। इसमें साफ कहा गया कि अब ऐसा कोई भी सामान भारत में आयात नहीं किया जा सकेगा जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से तैयार किया गया हो। यानी अगर जांच में यह पाया जाता है कि किसी उत्पाद को लोगों से उनकी इच्छा के खिलाफ धमकी देकर या दबाव डालकर बनवाया गया है तो भारत उस उत्पाद के आयात पर रोक लगा सकता है। सरकार ने फोर्स लेबर की परिभाषा भी वही अपनाई है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 1930 के कन्वेंशन में दी गई है। इससे भारत ने यह संकेत दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप अपना व्यापारिक ढांचा तैयार कर रहा है। लेकिन भारत सिर्फ नियम बनाकर नहीं रुका। अमेरिका की 301 जांच पर भी भारत ने खुलकर आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका में हुई सुनवाई के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस तरह के मामलों का समाधान एक तरफ़ा टेरिफ लगाकर नहीं बल्कि विपक्षीय व्यापार वार्ता के जरिए होना चाहिए। भारत ने अमेरिका के रवैया पर भी सवाल उठाए। भारतीय पक्ष ने कहा कि अमेरिका खुद लगभग 1600 उत्पादों को अपनी जांच के दायरे से बाहर रखता है। अगर उद्देश्य वास्तव में जबरन मजदूरी को रोकना है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर छूट क्यों दी जा रही है? भारत ने यह भी कहा कि अमेरिकी नीति कुछ मामलों में अपने ही उत्पादों को बढ़ावा देती है। इसलिए केवल दूसरे देशों पर अतिरिक्त टेररिफ लगाना उचित तरीका नहीं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने नियमों को और मजबूत किया। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रस्तावित टेरिफ पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। इस पूरे मामले का असर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी पड़ सकता है। दोनों देश इस समय एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

अग्निवीरों पर सेना का बड़ा भरोसा, स्थायी भर्ती बढ़ाने का प्रस्ताव

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ऐसे समय में जब अग्निपथ योजना के तहत तैयार हुआ अग्निवीरों का पहला बैच अपनी चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला है, तब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने भर्ती नीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। तीनों सेनाओं ने अधिक संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चार वर्षों के दौरान इन युवा योद्धाओं ने अपने अनुशासन, पराक्रम, तकनीकी दक्षता और युद्ध कौशल से सेनाओं का पूरा भरोसा जीत लिया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो भारत को आधुनिक युद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक युवा, तेज, तकनीक आधारित और प्रहारक सैन्य शक्ति मिलेगी। इसका सीधा संदेश भारत के दुश्मनों के लिए है कि सीमा पर अब ऐसी नई पीढ़ी तैनात होने जा रही है जो किसी भी दुस्साहस का त्वरित और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। हम आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक बैच के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन और संगठन की आवश्यकता के आधार पर स्थायी सेवा में शामिल किया जा सकता है। अब नौसेना ने इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि सेना और वायुसेना ने इसे 50 प्रतिशत तक ले जाने की मांग रखी है। यह मांग अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि चार वर्षों के प्रशिक्षण और सेवा के दौरान अग्निवीरों ने अपनी क्षमता, अनुशासन और युद्ध कौशल से सेनाओं का विश्वास जीता है।

UNSC सीट के लिए भारत का बड़ा मिशन, दुनिया के सामने रखा 'शांति' विजन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दुनिया में बढ़ते युद्ध, तनाव और अस्थिरता के बीच भारत ने वैश्विक शांति का एक नया मास्टर प्लान पेश कर दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से भारत ने साल 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अस्थाई सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार भारत का यह मिशन सिर्फ एक सदस्यता की होड़ नहीं है बल्कि यह दुनिया को जोड़ने वाला मिशन शांति है। इस राह में भारत के सामने मुस्लिम देशों के एक बड़े गुट की चुनौती है। लेकिन नई दिल्ली की चक्रव्यूह कूटनीति भी पूरी तरह तैयार है। जब पूरी दुनिया यूक्रेन संकट, मिडिल ईस्ट की आग और वैश्विक मंदी से करा रही है, तब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सभ्यतागत संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की इस दावेदारी के लिए शांति विज़न को ल्च किया है। शांति का पूरा नाम है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। यानी अंतरराष्ट्रीय नियमों, आपसी भरोसे और ईमानदारी के जरिए सबका सर्वांगीण विकास सुरक्षित करना। भारत ने इस मिशन के तहत दुनिया के सामने छह बड़ी प्राथमिकताएं रखी हैं। सबसे पहले ग्लोबल साउथ की आवाज। विकासशील और गरीब देशों का पुरजोर प्रतिनिधित्व करना। दूसरा है सुधारवादी बहुपक्षवाद रिफॉर्मड मल्टीलटरलिज्म संयुक्त राष्ट्र के पुराने ढांचे में बदलाव और यूएनएससी का विस्तार आधुनिक शांति सेना तकनीक से लैस यूएन शांति सेना तैयार करना एआई के खतरों से निपटना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए वैश्विक नियम बनाना समुद्री रास्तों की सुरक्षा अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का तक समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना आतंकवाद पर कड़ा प्रहार टेरर फंडिंग को रोकने के लिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूएन में एक विशेष कूटनीतिक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल मंच पर भारत का दावा बेहद मजबूती से रखा।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल, हजारों लोग सड़कों पर उतरे

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भले ही पाकिस्तान का प्रशासन पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (POK) में मौजूद 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) को हथियारों से लैस और "प्रतिबंधित" संगठन बताता हो, फिर भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती, खून-खराबे और बेरहम कार्रवाई के बावजूद इस ग्रुप ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। मंगलवार को कब्ज़ा करने वाले प्रशासन के सुरक्षा बलों और POK के लोगों के बीच हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो गई; इन घटनाओं ने बुधवार दोपहर मुज़फ़्फ़राबाद तक एक बड़े और अहम मार्च का रास्ता तैयार कर दिया है। POK के शहरों को सील कर दिया गया है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने पत्रकारों को रावलकोट शहर में घुसने से रोककर वहां बिना किसी औपचारिक घोषणा के मीडिया पर रोक लगा दी है। POK में पिछले एक महीने से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को भी वहां तनाव बना हुआ है। एक दिन पहले ही, रावलकोट से मुज़फ़्फ़राबाद (POK का प्रशासनिक केंद्र) तक JAAC के लॉन्ग मार्च से पहले हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दो सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, हज़ारों लोग अलग-अलग शहरों और कस्बों में जमा हुए हैं, जबकि JAAC नेताओं का दावा है कि कम से कम 40,000 प्रदर्शनकारियों ने मुज़फ़्फ़राबाद तक मार्च करने की योजना बनाई थी। यह ताज़ा हिंसा ऐसे समय में हुई है जब इस इलाके में सरकार के ख़िलाफ़ कई सालों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने विरोध मार्च को रोकने के लिए कम से कम 4,000 रेंजर्स, पुलिस और फ़्रंटियर कोर के जवानों को तैनात किया है। 1947 में पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े वाले भारतीय इलाके में अशांति बढ़ गई है। POK में प्रशासन, महंगाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हफ़्तों से चल रहे विरोध-प्रदर्शन अब और तेज़ हो गए हैं।

भारत के लिए अहम चाबहार पोर्ट पर फिर हमला, अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से भारी नुकसान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाला बंदरगाह चाबहार। इसे लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान से चल रहे युद्ध में अमेरिका और इजराइल चाबहार के कई इलाकों पर बमबारी कर चुका है और इसमें चाबहार के इलाकों में भारी नुकसान की भी खबरें हैं। लेकिन अब चाबाहार पर एक बार फिर हमले की खबर सामने आई है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम अफेयर्स अथॉरिटी ने बुधवार को बताया कि दक्षिण-पूर्वी ईरान में चाबहार पोर्ट पर रात में हुए हमलों के दौरान अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर हमला हुआ, जिससे उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। अथॉरिटी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमलों के बाद पोर्ट के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि मैरीटाइम वॉचटावर एक सिविलियन सुविधा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्र में मछुआरों के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन और

समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यह बयान फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें एक प्रांतीय अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुज़ेस्तान प्रांत में गेहूं के भंडारण वाले साइलो और एक अन्य जगह पर रात में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे और आने वाले दिनों में और तेज़ होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान बातचीत की मेज़ पर वापस नहीं लौटा, तो अमेरिका अगले हफ़्ते से ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। हाल के दिनों में होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए उस समझौते (MoU) के बावजूद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं, जिसका मकसद संघर्ष को खत्म करना और स्थायी शांति समझौता करना था। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उसने अमेरिका पर इस्लामाबाद समझौते (MoU) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

संपादक की कलम से

दुनिया तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के युग में प्रवेश कर चुकी है। आज AI केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, मीडिया और सरकारी सेवाओं तक अपनी पहुंच बना चुका है। भारत भी इस तकनीकी परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। एक ओर AI देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी ओर रोजगार, गोपनीयता और नैतिकता जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि AI को केवल तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के एक बड़े माध्यम के रूप में देखा जाए। AI का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जटिल कार्यों को कम समय में अधिक सटीकता के साथ पूरा करने में सक्षम है। अस्पतालों में बीमारियों की पहचान, किसानों के लिए मौसम और फसल संबंधी सलाह, छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में AI उल्लेखनीय बदलाव ला रहा है। भारत में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें भी AI आधारित नवाचारों को बढ़ावा दे रही हैं। इससे नए उद्योग विकसित हो रहे हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।हालांकि, AI के बढ़ते उपयोग के साथ रोजगार को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। कई ऐसे कार्य, जिन्हें पहले इंसान करते थे, अब मशीनें और सॉफ्टवेयर करने लगे हैं। ग्राहक सेवा, डेटा एंट्री, कंटेंट निर्माण और कई प्रशासनिक कार्यों में ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोजगार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, बल्कि रोजगार का स्वरूप बदलेगा। आने वाले समय में वही व्यक्ति अधिक सफल होगा, जो नई तकनीकों के साथ स्वयं को लगातार अपडेट करता रहेगा। इसलिए शिक्षा प्रणाली में भी डिजिटल कौशल, डेटा विश्लेषण और AI से जुड़ी जानकारी को प्राथमिकता देना समय की मांग है।एक और महत्वपूर्ण चिंता डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की है। AI जितना अधिक डेटा पर निर्भर करता है, उतना ही नागरिकों की निजी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि मजबूत कानूनी व्यवस्था और निगरानी तंत्र नहीं होगा, तो साइबर अपराध, फर्जी सूचनाएं और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए AI के विकास के साथ-साथ स्पष्ट नियम, जवाबदेही और नैतिक मानकों का निर्माण भी आवश्यक है।

ममता बनर्जी का BJP पर तीखा हमला,

बोलीं- 'तुम्हारा अंत देखे बिना नहीं मरूंगी'

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती थी उन्हें हार्ट अटैक आए। साथ ही, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार बताते हुए जनता से माफी भी मांगी।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा। उन्हें एक और झटका तब लगा जब विधायक मदन मित्रा बागी खेमे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, जो जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं और साथ ही कहा कि उनके पास BJP के लिए एक संदेश है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी चाहती थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि मुझे हार्ट अटैक आए, लेकिन मैं तब तक ज़िंदा रहूँगी जब तक आपका अंत न देख लूँ। बुधवार को मित्रा ने ममता का खेमा छोड़कर रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने "सिर्फ़ विधानसभा में अपना कमरा बदला है।" उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के "छह महीने के लिए पद से हटने" की उनकी मांग न माने जाने के बाद उन्होंने TMC छोड़ दी। उनके इस्तीफ़े पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने कहा कि मित्रा ने इसलिए पद छोड़ा क्योंकि ED ने मंगलवार को उनकी पत्नी और दो बेटों को समन भेजा था। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी का उनके इस फ़ैसले से कोई लेना-देना नहीं था। ममता ने कहा कि अभिषेक पार्टी पर हमलों के लिए एक बहाना बन गए हैं, जबकि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार समन भेजे गए हैं। उन्होंने समझौते के ज़रिए राहत पाने के बजाय राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के लिए उनकी तारीफ़ की। बुधवार को फ़ेसबुक लाइव के दौरान TMC प्रमुख ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को एक बहाना बना दिया गया है। उनके परिवार के सदस्यों को समन भेजे गए थे। अगर वह चाहते तो राहत पा सकते थे। लेकिन वह लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटे। जिस तरह से उन्होंने लड़ना जारी रखा है, उनकी सभी कमियों को माफ़ कर दिया गया है। पार्टी छोड़ने वालों की आलोचना करते हुए ममता ने कहा कि मैं इन गद्दारों की ओर से जनता से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए अपना विवेक (ज़मीर) नहीं बेचा है। TMC प्रमुख ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा अगर मैंने समझौता किया होता, तो हमें इतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। जिन लोगों ने समझौता किया है, उनके पास अपने कई बैग और सामान हैं। यह बात उन्होंने उन नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कही जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है। ममता ने आरोप लगाया कि BJP जांच एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल करके नेताओं को दल बदलने के लिए मजबूर कर रही है, और कई नेताओं ने डर के कारण पाला बदला है।

संजय राउत के आरोपों पर भड़के एकनाथ शिंदे, बोले- 'घटिया बातों का जवाब नहीं देता'

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत की टिप्पणियों को खारिज करते हुए उन्हें निचले स्तर का और जवाब देने लायक नहीं बताया। शिंदे का यह बयान राउत के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंज़ूरी लेने के लिए "चुराई हुई संपत्ति" – यानी अपने गुट को लेकर गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने कहा कि संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में मेरे प्रवक्ता ही जवाब देते हैं। मुझे ऐसी घटिया टिप्पणियों का जवाब देना सही नहीं लगता। उन्होंने शिवसेना के अपने गुट और UBT गुट के बीच अंतर बताते हुए कहा कि वे 'बर्बाद करने' की भाषा बोलते हैं, जबकि हम 'आगे बढ़ने और विकास करने' की बात करते हैं। वे चार साल से गालियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वे खुद के लिए ही और बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता मजबूती से हमारे साथ खड़ी है। गृह मंत्री से अपनी हालिया मुलाकात का मकसद बताते हुए शिंदे ने कहा कि उनके साथ छह सांसद भी थे, जो हाल ही में उनके गुट में शामिल हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने विकास कार्यों के लिए समर्थन मांगा और जोर देकर कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से गैर-राजनीतिक थी। शिंदे ने बताया कि हाल ही में छह सांसद शिवसेना में शामिल हुए हैं। हम अमित भाई से आशीर्वाद लेने और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव पेश करने के लिए उनसे मिलने गए थे। इनमें कृष्णा-मराठवाड़ा जैसी सिंचाई परियोजनाएं, साथ ही रेलवे, सड़क और मनरेगा (MGNREGA) व पीएम आवास योजना जैसी ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल हैं। अमित भाई ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे संबंधित मंत्रियों के साथ तालमेल बिठाकर इन मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले, संजय राउत ने शिंदे के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि क्या इस देश में अभी भी कानून का राज है? एकनाथ शिंदे दिल्ली की सड़कों पर वह चीज़ लेकर घूम रहे हैं जिसे मैं 'चोरी की संपत्ति' कहता हूँ, फिर भी कानून उन्हें रोकता नहीं है। वे मुंबई से यह 'चोरी का बंडल' देश के गृह मंत्री के पास ले गए हैं और कह रहे हैं, 'यह मेरी चोरी की संपत्ति है। कृपया इसे अपनी मंज़ूरी दें।' अगर गृह मंत्री ऐसे कामों का समर्थन करते हैं, तो मुझे कानून के राज की स्थिति को लेकर गहरी चिंता है।

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर घमासान, चन्नी-बाजवा की अहम मुलाकात

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित आवास पर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की। कांग्रेस नेतृत्व ने 1 जुलाई को घोषणा की कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। खबरों के अनुसार, चन्नी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं; कुछ वरिष्ठ नेता जालंधर के सांसद के अभियान का समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब के लिए AICC के इंचार्ज भूपेश बघेल ने कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को एक रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में वारिंग को ही राज्य अध्यक्ष बनाए रखने की सिफारिश की गई है, क्योंकि 29 में से 25 ज़िला अध्यक्ष और पंजाब के सात में से चार सांसद उनका समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में वेणुगोपाल से मिलने के बाद बघेल ने संकेत दिया कि पंजाब में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा; उन्होंने कहा, "यह बच्चों का खेल नहीं है।" उन्होंने चंडीगढ़ में भी ऐसी ही बात कही थी। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही है। चुनावों के लिए कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद, बघेल ने चंडीगढ़ में छह दिन बिताए और कई नेताओं से मुलाकात की। आखिरी दिन उन्होंने चन्नी के नेतृत्व वाले नाराज़ नेताओं के एक समूह से भी मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बदलाव की मांग करने के बाद, खबर है कि कांग्रेस आलाकमान अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की; इस बैठक में वेणुगोपाल भी शामिल हुए। बुधवार सुबह, बघेल से मिलने से पहले वेणुगोपाल ने पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की।

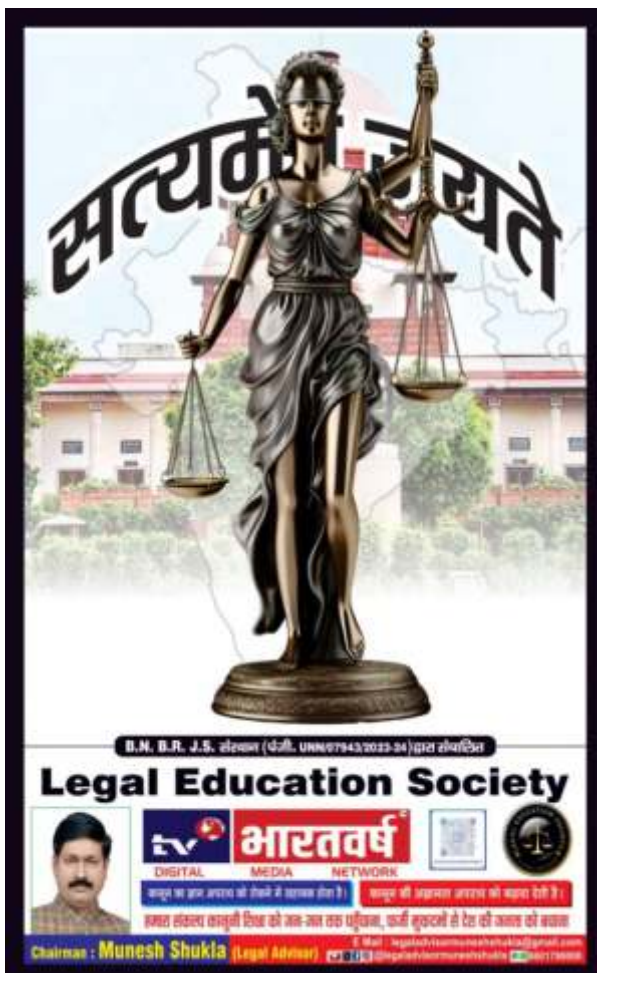

क्या सिर्फ LLB की डिग्री से बन जाते हैं वकील? जानिए कोर्ट में प्रैक्टिस के असली नियम

बहुत से लोग मानते हैं कि लॉ की डिग्री लेने से ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है लेकिन नियम अलग है। लॉयर और एडवोकेट में अंतर होता है और हर कोई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में वकालत से जुड़े कुछ नियम और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इससे ही तय होता है कि कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार किसे है। इन नियमों और प्रक्रियाओं को समझना ज्यूडिशियल एग्जाम के अलावा जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और कानून में रुचि रखने वालों के लिए यह टॉपिक समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर वकील और एडवोकेट को लेकर कन्फ्यूजन होता है। लॉयर को वकील भी कहा जाता है और यह एक लॉ प्रोफेशनल होता है। लॉयर के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून की डिग्री LLB होती है। लॉयर कानूनी मामलों में सलाह देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और दस्तावेज तैयार करते हैं। कोर्ट-कचहरी के बाहर के कानूनी मामलों में क्लाइंट की मदद करते हैं। वे लॉ फर्म, कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी विभागों, NGO में या कानूनी सलाहकार के तौर पर काम कर सकते हैं। एडवोकेट एक क्वालिफाइड वकील होता है, जिसने भारत में एडवोकेट्स एक्ट-1961 के तहत लॉ की डिग्री पूरी करने और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करने के बाद किसी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो। एडवोकेट को अदालतों और ट्रिब्यूनल में क्लाइंट का पक्ष रखने, केस पर बहस करने, सबूत पेश करने और अपने क्लाइंट के लिए न्याय की मांग करने का अधिकार होता है। वे कानूनी सलाह देने के साथ-साथ मुकदमेबाजी और कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। सिर्फ लॉ की डिग्री से कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार नहीं मिलता है। अक्सर लोग लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय कानूनी व्यवस्था में इन दोनों के बीच एक स्पष्ट और बड़ा तकनीकी अंतर है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 (Advocates Act-1961) के तहत एडवोकेट वह व्यक्ति है जो किसी राज्य की बार काउंसिल में दर्ज होता है और एडवोकेट के पास केस लड़ने का अधिकार होता है। यदि आपने कानून की डिग्री ले ली है तो आपको अदालत में वकालत करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आप को भारत के किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण (Registration) उसके बाद AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) जारी करता है। इसे आम बोलचाल में 'सनद' भी कहते हैं।

अमेरिका में स्प्रिंग इनटेक, एडमिशन एक्सपर्ट से समझें पूरा प्रोसेस

अमेरिका में जिस तरह फॉल इनटेक एडमिशन के लिए पॉपुलर है, वैसे ही स्प्रिंग इनटेक में भी दाखिले के लिए खूब आवेदन किए जाते हैं। ये इनटेक खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो फॉल में एडमिशन लेने से चूक गए या फिर जिनकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है और अब वे तुरंत एडमिशन चाहते हैं। स्प्रिंग इनटेक में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास की शुरुआत जनवरी से होती है।अगर आप भी स्प्रिंग इनटेक में दाखिला लेने वाले हैं, तो इसके बाद आपको खूब सारे पेपरवर्क से जूझना पड़ेगा। ये कई लोगों को कंफ्यूज भी कर देता है। SEVIS, I-20, DS-160 जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको खूब सुनने को मिलेगा, जो कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। कई बार स्टूडेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स को सही से समझ नहीं पाते हैं और समय पर वीजा आदि के लिए अप्लाई करने से रह जाते हैं। इससे उनका एडमिशन भी खतरे में आ जाता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि हर डॉक्यूमेंट असल में क्या काम करता है, तो पूरी प्रक्रिया समझ में आने लगती है। यह असल में एक चेन की तरह है, एक डॉक्यूमेंट से अगला डॉक्यूमेंट जुड़ा होता है और हर डॉक्यूमेंट का मकसद अमेरिकी सरकार को कोई खास बात साबित करना होता है। ऐसे में आज हम स्टेप-बाय-स्टेप इस चेन के बारे में जानेंगे, ताकि आपको पता रहे कि किस डॉक्यूमेंट का क्या काम है और कैसे इन्हें लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, अब यहां सवाल उठता है कि अमेरिका में पढ़ाई से जुड़े इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अमेरिकी सरकार इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए क्या समझना चाहती है? सरकार इन सभी दस्तावेजों के जरिए 3 प्रमुख चीजों के बारे में जानना चाहती है।

ICC का बड़ा ऐलान! 2027 विश्व कप में 14 टीमें, नया फॉर्मेट बढ़ाएगा रोमांच

भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव संभव, सहायक कोच छोड़ सकते हैं पद

भारतीय क्रिकेट टीम के सहयोगी दल में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूद जानकारी के अनुसार सहायक कोच रयान टेन डोएशेटे ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सामने टीम से अलग होने की इच्छा जताई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यदि बोर्ड और मुख्य कोच गौतम गंभीर इसकी मंजूरी देते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मुकाबले के बाद उनका भारतीय टीम के साथ सफर समाप्त हो सकता है। बता दें कि रयान टेन डोएशेटे लगभग दो वर्ष पहले भारतीय टीम के सहयोगी दल से जुड़े थे। नीदरलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे टेन डोएशेटे को गौतम गंभीर की सिफारिश पर टीम में शामिल किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार उनका शुरुआती अनुबंध भी अब पूरा हो चुका है और इसी वजह से वह अपने भविष्य को लेकर नया फैसला लेना चाहते है। गौरतलब है कि उनके इस फैसले के पीछे किसी तरह की असंतुष्टि या टीम के माहौल से जुड़ी कोई वजह नहीं बताई जा रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार वह पूरी तरह निजी और पारिवारिक कारणों से यह कदम उठाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उनके तीन छोटे बेटे हैं और उनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं। ऐसे में वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। चूंकि भारतीय टीम के साथ काम करने के दौरान लगातार विदेश यात्राएं और लंबे दौरे करने पड़ते हैं, इसलिए वह अब ऐसी जिम्मेदारी तलाश रहे हैं जिसमें यात्रा कम हो और परिवार के साथ अधिक समय मिल सके।

स्पेन से हार के बाद एम्बाप्पे का बड़ा बयान, बोले- रणनीति पर नहीं खेल पाए

विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस की टीम में निराशा साफ दिखाई दी। लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूटने के बाद कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने माना कि उनकी टीम मैच के दौरान अपनी तय रणनीति पर अमल नहीं कर सकी। उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीकी प्रदर्शन, सामूहिक खेल और मिडफील्ड की लड़ाई में स्पेन ने फ्रांस पर पूरी तरह बढ़त बना ली थी। बता दें कि डलास में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पूरे मुकाबले के दौरान स्पेन ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखा और फ्रांस को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर फ्रांस का आक्रमण भी उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ सका। मैच के बाद किलियन एम्बाप्पे ने कहा कि टीम ने वैसा खेल नहीं दिखाया, जिसकी तैयारी की गई थी। उनके अनुसार फ्रांस की योजना शुरुआत से ही स्पेन पर ऊंचे क्षेत्र में दबाव बनाने की थी, ताकि वह अपनी पसंद की धीमी और नियंत्रित लय में खेल न सके। लेकिन खिलाड़ी इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब विश्व कप के सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम अपनी योजना के अनुसार नहीं खेलती, तो जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले किलियन एम्बाप्पे इस विश्व कप के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने फ्रांस के लिए कुल आठ गोल किए और टीम को अंतिम चार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि सेमीफाइनल में स्पेन के मजबूत खेल के सामने वह भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल खेलने का उनका सपना अधूरा रह गया है।

अर्जेंटीना पर पक्षपात के आरोप, ऑनलाइन अभियान ने पकड़ी रफ्तार

विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबले को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। हालांकि मैच शुरू होने से पहले एक नया विवाद भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर अर्जेंटीना को लेकर रेफरी पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऑनलाइन याचिका भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अर्जेंटीना को विश्व कप से बाहर करने की मांग की गई है। हालांकि इन आरोपों या याचिका में किए गए दावों की किसी आधिकारिक संस्था या फीफा की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। मौजूद जानकारी के अनुसार अर्जेंटीना आउट नाम से चलाए जा रहे एक ऑनलाइन अभियान में दावा किया गया है कि फीफा और कुछ रेफरी अर्जेंटीना तथा उसके कप्तान लियोनेल मेसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। इसी आधार पर टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की मांग की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक बुधवार शाम तक इस ऑनलाइन याचिका पर एक करोड़ से अधिक हस्ताक्षर किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि यह संख्या स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सकी है और फीफा ने भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रेफरी के फैसलों को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। कई बार हारने वाली टीमों के समर्थक निर्णायक फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन किसी भी आरोप को सही मानने से पहले आधिकारिक जांच या संबंधित संस्था की पुष्टि का इंतजार करना जरूरी होता है। गौरतलब है कि मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में से एक मानी जाती है। दोनों देशों के बीच खेले गए मुकाबलों में कई यादगार घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप, जिसे स्पेनिश भाषा में माल्विनास कहा जाता है, को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक विवाद भी रहा है, जिसका असर कई बार खेल के माहौल में भी देखने को मिला है।

खेती ने बदली तकदीर

क्यों वियतनाम के किसान हैं अमीर?

जब खेती की बात होती है तो अक्सर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि क्या खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है? भारत समेत कई देशों में किसान मौसम, बढ़ती लागत और फसलों के कम दाम की वजह से परेशान रहते हैं. लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा देश भी है, जहां खेती ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी. यह देश है वियतनाम. आज वियतनाम के किसान सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी अनाज, कॉफी, काजू और काली मिर्च पैदा करते हैं. यही वजह है कि वहां के कई किसानों की आय पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है. हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि वहां का हर किसान अमीर है, लेकिन खेती के बेहतर तरीकों ने बड़ी संख्या में किसानों की आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत की है.

एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर कपल का खतरनाक इश्क

1,454 फीट की ऊंचाई पर प्रपोजल

किसी ने समुद्र किनारे प्रपोज किया, किसी ने बर्फीले पहाड़ों पर, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने 1,454 फीट (443 मीटर) की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक की चोटी पर घुटनों के बल बैठकर अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज किया हो? सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह हकीकत है. यही वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो करोड़ों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक कपल मौत को मात देता नजर आता है और अगले ही पल प्यार का इजहार करता है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इस रोमांटिक पल के कुछ ही देर बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त में पहुंच जाते हैं. तो आखिर ये कपल कौन है? इन्होंने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? और क्या सिर्फ एक प्रपोजल के लिए किसी की जान दांव पर लग सकती है? वीडियो में नजर आने वाले कपल हैं 33 वर्षीय एंजेला निकोलाउ और 32 वर्षीय इवान बीर्कुस (वान्या). अगर आप सोशल मीडिया पर एडवेंचर वीडियो देखते हैं, तो संभव है कि आपने इन दोनों को पहले भी देखा हो. पिछले 10 साल से दोनों दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों, क्रेनों और टावरों पर बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के चढ़ते रहे हैं.

रास्ता चुन लेते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक ठगी का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित बनकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली मिस्र की लाख रुपये की मदद जुटाई, जबकि उन्हें कभी कैंसर था ही नहीं.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनिया फौद सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर करती थीं, जिनमें वह खुद को को शक होने लगा, जब उनकी महंगी लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे. डोनिया फौद डोनेशन में मिले पैसों से उन्होंने कार खरीदी, फ्लैट लिया और कई लग्जरी से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. रिपोर्ट में न कीमोथेरेपी का जिक्र था और न ही रेडिएशन का. बताया गया कि डोनिया को सिर्फ कुछ सामान्य स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें थीं, जिनका इलाज चल रहा था.

क मुताबिक घूमना, हर चीज अनुमानित और व्यवस्थित, लेकिन कुछ कमी लगती थी भारत में ट्रैफिक है, प्रदूषण है, शोर है, भीड़ है, अनिश्चितता है... फिर भी यहां कुछ है जो वहां नहीं मिलता.

'धमाल 4' Vs 'वेलकम 3' के बीच फंसी 'अल्फा'

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. 4 जुलाई 2026 को रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' पहले से ही टिकट खिड़की पर कब्जा जमाए बैठी है. वहीं 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई अजय देवगन की 'धमाल 4' ने आते ही कमाई की रफ्तार तेज कर दी है. इसके बीच 3 जुलाई को रिलीज हुई 'अल्फा' भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, जिससे बॉक्स ऑफिस की जंग और दिलचस्प हो गई है. धमाल 4' ने पहले दिन 14 करोड़ रुपये से ओपनिंग की और दूसरे दिन करीब 22.50 करोड़ रुपये बटोर लिए. यानी सिर्फ दो दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 36.50 करोड़ रुपये पहुंच गया. फैमिली ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और अगर रविवार को भी यही रफ्तार बनी रहती है तो फिल्म आराम से 55 करोड़ रुपये से ज्यादा का ओपनिंग वीकेंड निकाल सकती है. अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. वहीं 'वेलकम टू द जंगल' दूसरे हफ्ते में भी मजबूती से डटी हुई है. फिल्म ने दूसरे शुक्रवार 4.95 करोड़, शनिवार 7.92 करोड़, रविवार 10.44 करोड़, सोमवार 2.78 करोड़, मंगलवार 3.21 करोड़, बुधवार 2.28 करोड़ और गुरुवार 2.11 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे हफ्ते का कुल कलेक्शन 33.69 करोड़ रुपये रहा. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 128.90 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. साफ है कि नए-नवेले मुकाबले के बावजूद 'वेलकम टू द जंगल' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन समेत 32 स्टार कास्ट की फौज शामिल है. अगर 'अल्फा' की बात करें तो फिल्म की शुरुआत ठीक-ठाक रही. आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस फिल्म ने पहले वीकेंड में करीब 33 करोड़ रुपये का इंडिया नेट बिजनेस किया था, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 79 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई थी. हालांकि अब 'धमाल 4' की एंट्री के बाद 'अल्फा' के सामने स्क्रीन और दर्शकों दोनों की चुनौती बढ़ गई है. और अब ये दर्शकों को खींच पाने में स्ट्रगल करती दिख रही हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या नहीं. फिलहाल अगर बॉक्स ऑफिस की रेस देखें तो कुल कमाई के मामले में 'वेलकम टू द जंगल' सबसे आगे है. वहीं 'धमाल 4' ने सिर्फ दो दिनों में शानदार शुरुआत करके यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वह बड़ी चुनौती बनने वाली है. अब असली खेल सोमवार से शुरू होगा, जब पता चलेगा कि दर्शकों का प्यार किस फिल्म के साथ सबसे लंबे समय तक बना रहता है.

'वाराणसी' को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

महेश बाबू बनेंगे राम

हैदराबाद। निर्देशक एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म की कहानी, इसके भव्य सेट और स्टारकास्ट को लेकर पहले से ही चर्चाओं का दौर जारी था, लेकिन अब राजामौली के पिता और प्रसिद्ध पटकथा लेखक के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ने फिल्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर प्रशंसकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। एक हालिया कार्यक्रम में विजयेंद्र प्रसाद ने खुलासा किया कि फिल्म में लगभग 30 मिनट लंबा एक भव्य और रोमांचक युद्ध दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच संघर्ष को दर्शाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह दृश्य भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार और दृश्यात्मक रूप से शानदार सीक्वेंस में से एक साबित हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि यह लंबा सीक्वेंस पौराणिक है या राजनीतिक, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राम और कुंभकर्ण के बीच की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि फिल्म के शुरुआती प्रचार सामग्री और विजुअल्स में दर्शकों को इसके कुछ संकेत पहले ही मिल चुके हैं। विजयेंद्र प्रसाद के अनुसार, इस युद्ध दृश्य को अत्यंत भव्यता और तकनीकी उत्कृष्टता के साथ फिल्माया गया है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि दक्षिण भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू इस किरदार में नजर आएंगे। राजामौली भी पहले एक कार्यक्रम में महेश बाबू के लुक की जमकर प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जब पहली बार महेश बाबू राम के वेश में फोटोशूट के लिए सामने आए, तो उन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। राजामौली ने कहा था कि महेश बाबू में जहां भगवान कृष्ण जैसी आकर्षक व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है, वहीं उनके चेहरे पर भगवान राम जैसी शांति और गंभीरता भी नजर आती है। निर्देशक ने यहां तक खुलासा किया था कि उन्होंने महेश बाबू के राम अवतार वाली तस्वीर को कुछ समय के लिए अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी बनाया था, हालांकि बाद में गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे हटा दिया। फिल्म के चर्चित युद्ध दृश्य को लेकर राजामौली ने बताया कि इसकी शूटिंग लगभग 60 दिनों तक चली। उनके अनुसार, इस सीक्वेंस का हर हिस्सा अपने आप में एक अलग फिल्म जैसा था। शूटिंग के दौरान कई तकनीकी और रचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः पूरी टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनका मानना है कि यह दृश्य उनके करियर के सबसे यादगार फिल्मी क्षणों में शामिल होगा। फिल्म को लेकर पहले ऐसी चर्चाएं थीं कि इसकी कहानी टाइम ट्रैवल की अवधारणा पर आधारित हो सकती है, लेकिन अब रामायण से जुड़े तत्वों के सामने आने के बाद दर्शकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है। फिल्म में महेश बाबू के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। फिल्म के वर्ष 2027 में रिलीज होने की संभावना है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।

69000 शिक्षक भर्ती पर फिर गरमाई सियासत, न्याय की मांग लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दिए आश्वासन के बावजूद नई चयन सूची जारी करने में देरी का आरोप लगाया।

उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन और नई चयन सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने निदेशालय के मुख्य द्वार के सामने नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार चयन सूची का पुनरीक्षण (री-विजिट) करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा था। अभ्यर्थियों के अनुसार यह समय सीमा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक नई चयन सूची जारी नहीं की गई है और न ही पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में वे नहीं चाहते कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की देरी या लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अदालत में किए गए वादे के अनुरूप सरकार शीघ्र नई चयन सूची तैयार कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करे। धरने में शामिल अभ्यर्थी विक्रम और अमित मौर्य ने बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। उनका कहना था कि इस मुद्दे को लेकर पिछले लगभग छह वर्षों से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों का सही तरीके से पालन न होने के कारण अनेक पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 को अपने महत्वपूर्ण आदेश में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करने तथा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार दलित और पिछड़े वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में अनावश्यक देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया होता, तो अभ्यर्थियों को दोबारा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने सरकार से न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने और सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की।धरना-प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य केवल आरक्षण नियमों का विधिसम्मत पालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और उससे पहले सरकार की संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

सिम बंद होते ही खाते से उड़ गए साढ़े चार लाख रुपये

लखनऊ में हरिद्वार यात्रा के दौरान एक फोन कॉल के बाद मोहनलालगंज निवासी युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने पहले उसका मोबाइल सिम बंद कराया और फिर दो बैंक खातों से 16 दिन में करीब 4.50 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित को किसी भी ट्रांजैक्शन का एसएमएस तक नहीं मिला। मामले में मोहनलालगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम कुढ़ा निवासी संदीप कुमार के मुताबिक वह 3 जून को हरिद्वार गए थे। वहीं एक अंजान व्यक्ति ने फोन कर कहा कि उनके नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, उसे बता दें, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। संदीप ने ओटीपी देने से इनकार कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद उनका मोबाइल सिम काम करना बंद कर गया। पीड़ित का आरोप है कि सिम बंद होने के बाद साइबर ठगों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मोहनलालगंज शाखा में मौजूद उनके दो खातों तक पहुंच बना ली। 5 जून से 21 जून के बीच अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर करीब 4.50 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस दौरान उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से कोई मैसेज या ओटीपी नहीं आया। बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने पर खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। इसके बाद संदीप ने मोहनलालगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है।

चकबंदी घोटाले के आरोप, किसानों ने आयुक्त कार्यालय का किया घेराव

बांदा में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों का विरोध अब लखनऊ तक पहुंच गया है। मंगलवार को किसानों ने लखनऊ स्थित चकबंदी आयुक्त कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में चकबंदी आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान नियमों की अनदेखी की गई, रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और भ्रष्टाचार के कारण किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उनका कहना है कि इन अनियमितताओं से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बांदा के अमलीकोर समेत सिलेहटा, बहिंगा, खटीटाखुर्द और महबरा गांवों में चकबंदी के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। मंडलायुक्त और चकबंदी निदेशालय स्तर पर पहले से गठित जांच समितियों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की जांच राजस्व परिषद की स्वतंत्र टीम से कराने की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम अमलीकोर में चक सीमांकन का करीब 40 प्रतिशत काम ही हुआ था, लेकिन शासन को कार्य पूरा होने की सूचना भेज दी गई। आरोप है कि कब्जा परिवर्तन और अन्य कार्रवाई भी अधूरे सीमांकन के आधार पर की गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। ज्ञापन में चकबंदी विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमों के विपरीत आदेश पारित करने, फर्जी अभिलेख तैयार करने, रिश्वत लेने, नामांतरण में गड़बड़ी करने और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पूर्व की जांच रिपोर्टों पर भी अमल न होने की बात कही गई है।

लखनऊ में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत

राजधानी लखनऊ में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ले ली। सुबह से तेज धूप और उमस के बीच दोपहर करीब तीन बजे आसमान में घने बादल छा गए। इसके कुछ ही मिनट बाद, लगभग 3:15 बजे शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो शाम 4:46 बजे तक रुक-रुककर तेज़ी से होती रही। अचानक हुई इस बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली। सड़क पर चल रहे राहगीरों और वाहन चालकों को शुरुआत में असुविधा हुई, लेकिन मौसम सुहाना होने से लोगों के चेहरे खिल उठे।मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों से शहर में बारिश नहीं हुई थी, जिससे तापमान और उमस लगातार बढ़ रही थी। मंगलवार को अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अधिकतम आर्द्रता 78 प्रतिशत तथा न्यूनतम 56 प्रतिशत रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवती घायल, जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित समता मूलक चौराहे पर रविवार शाम मामूली कहासुनी के बाद एक युवती ने स्कूटी सवार 2 सहेलियों पर कार चढ़ा दी। उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई। सहेली के परिजनों का आरोप है कि कार चला रही युवती नशे में थी और कार में शराब की बोतलें भी रखी थीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अलीगंज निवासी बबिता सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी नैना सिंह (27) अपनी सहेली के साथ एक्टिवा से समता मूलक चौराहे की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक कार सवार युवती से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि कार सवार युवती ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अब देख, तेरे साथ क्या करती हूं। बबिता सिंह के मुताबिक, इसके बाद जैसे ही नैना एक्टिवा लेकर आगे बढ़ी, कार सवार युवती ने पीछे से टक्कर मारते हुए गाड़ी उसकी एक्टिवा पर चढ़ा दी। हादसे में नैना कार के नीचे दब गई, जबकि एक्टिवा कार के पहिए में फंस गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह कार हटाकर नैना को बाहर निकाला। इस दौरान भी कार सवार युवती गाली-गलौज करती रही।

गलत तरीके से बढ़े बिजली लोड पर व्यापारियों का विरोध

लखनऊ परिक्षेत्र व्यापार मंडल ने मंगलवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के खिलाफ तालकटोरा स्थित एवरेडी के पास उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई प्रतिष्ठानों के बिजली मीटर का लोड उपभोक्ताओं की अनुमति और उचित जांच के बिना बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शन के बाद संगठन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस प्रदर्शन में लखनऊ परिक्षेत्र के सभी 22 व्यापार मंडलों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता ने कहा कि गलत तरीके से बढ़ाए गए बिजली लोड के कारण व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। व्यापार मंडल ने मांग की है कि शहर के सभी बाजारों में लगे बिजली मीटरों की दोबारा जांच कराई जाए। इसके आधार पर जरूरत के अनुसार लोड तय किया जाए। संगठन ने यह भी मांग की कि जिन उपभोक्ताओं का लोड गलत तरीके से बढ़ाया गया है, उसे तुरंत कम किया जाए और उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस की जाए। साथ ही, सभी शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाए।

संगठन ने 1912 हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। व्यापारियों का कहना था कि शिकायत दर्ज होने के चार घंटे के भीतर समाधान का दावा किया जाता है, लेकिन कई मामलों में 24 से 48 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि सभी उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं की शिकायतें मैन्युअल रूप से दर्ज करने की पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से सवाल किया कि यदि डिजिटल प्रणाली से बिजली का लोड स्वतः बढ़ाया जा सकता है, तो बिजली की कम खपत होने पर लोड स्वतः कम क्यों नहीं किया जाता। संगठन ने इस संबंध में स्पष्ट नीति और दिशा-निर्देश सार्वजनिक करने की मांग की।

तीन साल बाद भी अधूरा आनंद घाट, गंगा आरती का सपना अटका

उन्नाव के गंगाघाट स्थित आनंद घाट पर बनारस की तर्ज पर बन रहा भव्य गंगा आरती स्थल तीन साल बाद भी अधूरा है। पर्यटन विभाग की धीमी कार्यशैली और लगातार देरी के कारण यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। हाल ही में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निर्माण कार्य एक बार फिर प्रभावित हो गया है। इस परियोजना को आनंद घाट को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में स्वीकृति मिली थी। इसका लक्ष्य वाराणसी की तर्ज पर एक भव्य गंगा आरती स्थल बनाना था, ताकि स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं-पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। परियोजना पर काम 2023 के अंत में शुरू हुआ था, लेकिन यह निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कई बार दावा किया था कि निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि, जमीनी स्तर पर काम की गति धीमी रही। अब गंगा में आई बाढ़ के कारण निर्माण स्थल तक पानी पहुंच गया है, जिससे कार्य पूरी तरह बाधित हो गया है। निर्माण एजेंसियों को अब सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य में तेजी लाई जाती, तो आनंद घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन अब तक शुरू हो चुका होता। उनका मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व कई गुना बढ़ जाता, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता। क्षेत्रवासियों ने पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी नहीं की गई, जिससे परियोजना के पूरा होने में समय और लागत दोनों प्रभावित हुए हैं। लोगों ने शासन और पर्यटन विभाग से मांग की है कि बाढ़ का पानी उतरते ही निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर शुरू कराया जाए और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि आनंद घाट पर भव्य आरती स्थल बनने से उन्नाव को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और गंगा तट पर श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षक एवं व्यवस्थित स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

दलित युवकों से मारपीट के आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

उन्नाव के बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर गांव में तीन दलित युवकों के साथ कथित मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक और भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्राधिकारी (सीओ) बीघापुर से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ितों में रानीपुर गांव के रोहित कुमार, चिराग और अनुज कुमार शामिल हैं। उनका आरोप है कि 12 जुलाई को शाम करीब 4:30 बजे गांव के ही फुरकान और रमजानी ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ितों ने यह भी बताया कि आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने पीड़ित युवकों के साथ सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि यदि दलित युवकों के साथ अन्याय हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

विद्यालय की अनूठी पहल, बच्चों ने सीखा प्रकृति का महत्व

उन्नाव के बांगरमऊ विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बांगरमऊ ग्रामीण में मंगलवार को "हरियाली शिक्षण अभियान" के तहत अनूठा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। "पार्टी आम की, बातें काम की" थीम पर हुए इस आयोजन में बच्चों को कच्चे आम के माध्यम से पेड़ों और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान शिक्षिका सेविना दीक्षित ने बच्चों को कच्चा आम वितरित कर की। उन्होंने बच्चों से आम और पेड़ों से जुड़े सवाल पूछे और फिर पेड़ों की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेड़ केवल फल ही नहीं देते, बल्कि स्वच्छ हवा, छाया और जीवनदायी ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए पौधे लगाना जितना जरूरी है, उनकी नियमित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे फलों के बीजों को फेंकने के बजाय खाली स्थानों पर बोएंगे, ताकि अधिक से अधिक पौधे तैयार हो सकें। विद्यालय परिसर में "पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ" अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद सभासद गुड़िया, हफीज जी, हिमांशी सिंह, ज्योति मिश्रा, सोनम पांडे, रंजना त्रिवेदी, शना परवीन, उपासना और सुशीला देवी ने बच्चों को "एक पेड़ मां के नाम" अभियान से जुड़ने और घर पर पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के संस्कार विकसित किए जाएं तो भविष्य की पीढ़ियां हरियाली और स्वच्छ वातावरण के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। विद्यालय की इस पहल की अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हुए पौधरोपण और बीज संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था।

जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं, राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना

उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनका आरोप था कि अतीत में दोनों दलों का राम मंदिर के प्रति रुख पूरी तरह विरोध का रहा है, जबकि अब वे राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। सांसद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। उन्होंने कहा कि उस घटना में रामभक्तों के साथ अन्याय हुआ था और आज वही लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और न्यायालय में इसे रोकने के प्रयास किए थे। साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्ष का बदला हुआ रुख आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनाई गई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है।

सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर तकनीकी खराबी, घंटों थमा यातायात

उन्नाव में लखनऊ-कानपुर रेल मार्ग स्थित सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर मंगलवार सुबह गेट बूम में तकनीकी खराबी आने से करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस समस्या के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तेज धूप में फंसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के दौरान कानपुर की ओर मरीज लेकर जा रही एक एंबुलेंस भी फंस गई। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल पहल की। काफी मशक्कत के बाद गेट बूम को मैनुअल तरीके से ऊपर उठाकर एंबुलेंस को रेलवे ट्रैक पार कराया गया, जिसके बाद वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी। गेट बूम में खराबी की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। दोपहर करीब एक बजे तकनीकी खराबी दूर होने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। इस दौरान रेलवे कर्मचारी मैनुअल तरीके से फाटक का संचालन करते रहे। घटना का असर रेल संचालन पर भी पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को क्रॉसिंग से धीमी गति से गुजरने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि गेट बूम की तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए संबंधित उपकरणों की जांच और आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी।

शांति और सुरक्षा के बीच निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा

उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार दोपहर क्षेत्राधिकारी (सीओ) नगर विनी सिंह ने थाना गंगाघाट में बैठक की। इसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, रथ यात्रा के संयोजक वीरेंद्र शुक्ला और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीओ नगर ने आयोजकों के साथ रथ यात्रा के मार्ग, संभावित श्रद्धालुओं की संख्या, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण जैसे सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सभी से आपसी समन्वय बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बैठक के बाद सीओ विनी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और आयोजकों के साथ प्रस्तावित रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, संवेदनशील स्थलों और यातायात संचालन का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने सूचित किया कि यात्रा के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन भी किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को असुविधा न हो। आयोजकों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि रथ यात्रा के दौरान सभी स्वयंसेवक अनुशासन बनाए रखेंगे और पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। श्रद्धालुओं से भी शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है।

उत्तर प्रदेश को मिली 60 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात,

हर जिला मुख्यालय फोरलेन से जुड़ेगा: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश की 60 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हर जिला मुख्यालय फोरलेन और पांच लाख आबादी वाले प्रत्येक शहर को बाईपास मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर और दक्षिण उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर सड़क संपर्क विकसित किया जाएगा। साथ ही, पांच लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में बाईपास और हर जिला मुख्यालय को फोरलेन सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।कार्यक्रम के तहत कानपुर-लखनऊ सिक्स लेन एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया, जबकि हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (पैकेज-4) के फोरलेन निर्माण कार्य का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने वाले फोरलेन फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उन्नाव में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा के बाद करीब 60 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक उत्कृष्ट सड़क संपर्क पहले ही विकसित हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण हैं। अब उत्तर से दक्षिण तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहरों में यातायात का दबाव कम होगा। वहीं, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ने की योजना भी जल्द धरातल पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्य संस्कृति में विकास योजनाओं के लिए 'ना' शब्द का स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि गडकरी बड़े से बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए हमेशा सक्रिय और प्रतिबद्ध रहते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी बीमारू राज्य के रूप में पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन और बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण नई पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश पहचान के संकट, दंगों और अव्यवस्था से जूझता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विकास और निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा और सबसे अधिक संचालित एयरपोर्ट वाला राज्य बनकर उभरा है।

जीएसटी विभाग में IAS तैनाती पर घमासान, अधिकारियों ने सीएम से लगाई गुहार

उत्तर प्रदेश के राज्य कर (GST) विभाग में स्वीकृत पदों से अधिक आईएएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग के अधिकारियों और जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन का आरोप है कि विभाग में सेवा नियमावली की अनदेखी करते हुए ऐसे पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जो नियमानुसार केवल विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभागीय हलकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभागों में गिना जाता है। विभाग हर वर्ष करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये का राजस्व राज्य सरकार के खजाने में जमा कराता है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण विभाग को प्रशासनिक प्रशिक्षण का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यहां कार्य करने के लिए कर कानूनों, जीएसटी प्रणाली, व्यापारिक प्रक्रियाओं और राजस्व प्रशासन का गहन अनुभव आवश्यक होता है, जिसे विभागीय अधिकारी वर्षों की सेवा के बाद प्राप्त करते हैं।

'अखिलेश के बिना कांग्रेस जीरो',

रायबरेली में सपा सांसद एसपी सिंह का बड़ा हमला

रायबरेली में समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी सीटें बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस से जीरो है। इनको 50 से ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ से सांसद एसपी सिंह रायबरेली निजी कार्यक्रम में आए थे। जहां वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ओपी राजभर पर भी बड़ा बयान दिया है। बोले उन्हें जो कहा जाता है बोल देते हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सपा सांसद एसपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस भी भाजपा से मिली हुई है। सबको पता है कि पहले इसके पहले कांग्रेस के पास कितने विधायक और कितने सांसद थे? राहुल गांधी खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। अखिलेश के साथ चुनाव गठबंधन के कारण कांग्रेस को लाभ मिला और इसीलिए इतनी सीटें निकल आई थी। इस प्रकार का बयान देकर गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर हालत में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' से बचेगा समय और पैसा केशव प्रसाद मौर्य

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो इससे देश का समय और जनता का पैसा दोनों बचेंगे। साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' देश के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि आजादी के शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे।उन्होंने आरोप लगाया कि बाद के वर्षों में अलग-अलग राज्यों की सरकारों को समय से पहले हटाने जैसी घटनाओं के कारण चुनावी प्रक्रिया का पूरा ढांचा बदल गया। इसके चलते अब अलग-अलग समय पर चुनाव कराना पड़ता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। उनके मुताबिक, चुनावों में खर्च होने वाला पैसा अगर विकास कार्यों पर लगाया जाए, तो गरीबों, किसानों और आम लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने की वजह से सरकारी मशीनरी भी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है, जिससे कई विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किए गए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के विजन का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था देश के भविष्य के लिए जरूरी है और इसे लागू किया जाना चाहिए।